

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा - क्या महिला को मिल सकता है तीन तलाक स्वीकार ना करने का अधिकार?

तीन तलाक सुनवाई



नई दिल्ली: सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एआईएमपीएलबी से पूछा कि क्या ये मुमकिन है कि हम महिला को यह अधिकार दे दिया जाए कि वह तुरंत तौर पर दिये गये तलाक को स्वीकार ना करें। इस क्लॉज को निकाहनामा में भी शामिल किया जा सकता है। जिसमें कहा गया है कि तीन तलाक के तुरंत बाद भी शादी नहीं टूट सकती है। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे को तभी लागू किया जा सकता है जब काजी इस मुद्दे को जमीनी स्तर तक लागू करें, हालांकि ए आई एम पी एल बी की ओर से युसुफ हातमि ने कहा कि ए आई एम पी एल बी की एडवाइजरी को मानना सभी काजी के लिए जरूरी नहीं है। हालांकि वे हमारे सुझाव को मान सकते हैं। बोर्ड ने कोर्ट को 14 अप्रैल 2017 को पास किये गए एक फैसले के

बारे में भी बताया, जिसमें कहा गया था कि ट्रिपल तलाक के एक पाप है, और ऐसा करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि तीन तलाक का पिछले 1400 साल से जारी है। अगर राम का अयोध्या में जन्म होना, आस्था का विषय हो सकता है तो तीन तलाक का मुद्दा क्यों नहीं। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस्लाम धर्म ने महिलाओं को काफी पहले ही अधिकार दिये हुए हैं, परिवार और पर्सनल लॉ सविधान के तहत हैं, यह व्यक्तिगत आस्था का विषय है, जस्टिस कुरियन जोसेफ ने जब कपिल सिब्बल से पूछा कि क्या कोई ई-तलाक जैसी भी चीज है।

लाएंगे नया कानून-केन्द्र

इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह समय की कमी के कारण सिर्फ तीन तलाक के मुद्दे पर ही सुनवाई करेगी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि बहुविवाह और निकाह हलाला के मुद्दे पर भी सुनवाई का रास्ता भविष्य के लिए खुला है, केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि अगर शीर्ष अदालत तीन तलाक सहित तलाक के सभी तरीकों को निरस्त कर देती है तो मुस्लिम समाज में शादी और तलाक के नियमन के लिए नया कानून लाया जाया जाएगा। केंद्र ने यह भी आग्रह किया कि बहुविवाह और निकाह हलाला के मुद्दों को मौजूदा सुनवाई से अलग नहीं किया जाना चाहिए, इस पर सर्वोच्च अदालत ने भरोसा दिया कि ये सभी पहलू अपनी जगह मौजूद हैं और इन पर बाद में गौर किया जाएगा।

क्यों नहीं खत्म कर सकते तीन तलाक?

सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर सऊदी अरब, ईरान, इराक, लीबिया, मिस्र और सूडान जैसे देश तीन तलाक जैसे कानून को खत्म कर चुके हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा, अगर अदालत तुरंत तलाक के तरीके को निरस्त कर देती है तो हम लोगों को अलग-थलग नहीं छोड़ेंगे, हम मुस्लिम समुदाय के बीच शादी और तलाक के नियमन के लिए एक कानून लाएंगे। आपको बता दें कि ट्रिपल तलाक को लेकर 11 मई से सुनवाई चल रही है, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम सिर्फ ये समीक्षा करेंगे कि तलाक-ए-बिद्दत यानी एक बार में तीन तलाक और निकाह हलाला इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग है या नहीं, कोर्ट इस मुद्दे को इस नजर से भी देखेगा कि क्या तीन तलाक से मुस्लिम महिलाओं के मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है या नहीं। जारी है अभी भी सुनवाई।

लापता बालक बालिकाओं को तलाश करने का अभियान



न्यायसाक्षी @रायगढ़। अरसे से लापता एवं अपहृत बालक बालिकाओं की तलाश करने का विशेष अभियान दिनांक 15 मई से 15 जून तक चलाया जा रहा है इस सिलसिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री बी.एन.मीणा ने आज संबन्धित थाना प्रभारियों, महिला बाल विकास, खेल एवं युवक कल्याण, श्रम विभाग, समाज कल्याण तथा चाइल्ड लाइन से जुड़े सर्व संबंधितों की बैठक आज

माइनिंग के छापे से रेत

न्यायसाक्षी @रायगढ़। खनिज विभाग की टीम ने आज रेत माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुये ठाकुर पोड़ी में मांड नदी में छापा मारकर 3 ट्रेक्टरों को रेत का अवैध परिवहन करते पकड़ा जिनको ग्राम पंचायत ठाकुर पोड़ी, थाना कापू परिसर में सरपंच के सुपुर्द में दिया गया है। इस कार्यवाही में खनिज निरीक्षक अनिल साहू

पुलिस अधीक्षक कार्यालय म संपन्न हुई। बैठक में अपहृत बालक बालिकाओं के दस्तयाबी हेतु 55 सदस्यीय जिला स्तरीय टीम का गठन किया गया। जिले में अब तक के अपहृत लापता बालक बालिकाओं की सूची स्थानीय पैरालीगल वालेंटियर्स, महिला एवं बाल विकास, श्रम समाज कल्याण विभाग को भी जानकारी साझा करते हुए दस्तयाबी किए जाने की रणनीति बनाई गयी। बैठक में निर्णय लिया गया अपने एवं लापता बालक बालिकाओं के ऐसे प्रकरण जिनकी 120 दिनों तक पतासाजी नहीं मिल पाती ऐसे प्रकरण अनुसंधान हेतु ब्रूमन ट्रेकिंग यूनिट सेल को दिया जाए जिसका पर्यवेक्षण किया जावेगा।

माफियाओं में हड़कम्प

भरत लाल बंजारे, सुपरवाइजर सुनीलदत्त शर्मा शामिल थे। खनिज विभाग के छापे से अवैध कार्य करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ दिन पहले ही माइनिंग विभाग ने अवैध पत्थर उत्खनन करने वालों को शिकंसे में कसा था। उसके बाद इस कार्यवाही ने रेत माफियाओं के हौसले परत होने की उम्मीद है।

टोनही प्रताड़ना के 9 आरोपियों को 3-3 वर्ष की कैद

बिलासपुर। न्यायालय ने ग्रामीण को टोनहा कहकर प्रताड़ित करने और खुदकुशी के लिए मजबूर करने के 9 आरोपियों को 3-3 वर्ष कैद की सुनाई है। साथ ही अर्थदंड लगाया है। मस्तूरी थाना क्षेत्र के वेद परसदा में 14 अप्रैल 2007 की रत पंचायत बुलाई गई। आरोपी सरपंच पति रामकुमार पिता टेगू मेहर, अजय सिंह पिता जयराम सिंह, मनमोहन दास पिता लालदास, पुतन दुबे पिता धनेश्वर, प्रेम दास पिता लालदास, देवनाथ पिता कुन्जराम बरेठ, मुकेश पिता भुखा बरेठ, जगमोहन पिता लालदास एवं शंकर लाल साहू पिता पितर्द लाल ने गांव में रहने वाले पुनीराम केवट को टोनहा और उसकी बहन धनिया बाई को टोनही कहते हुए अपमानित किया। आरोपियों ने पुनीराम पर

5 हजार और धनिया बाई पर 500 रुपए अर्थदंड लगाया। पुनीराम ने अर्थदंड का भुगतान कर दिया। अगली सुबह उठकर वह घर से बाहर निकला। गांव के बाहर उसकी फांसी में लटकी लाश मिली। मस्तूरी पुलिस ने धारा 384 एवं धारा 5 टोनही प्रताड़ना एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रतीक्षा शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। न्यायालय ने अपराध सिद्ध होने पर आरोपियों को 3-3 वर्ष कैद, तीन आरोपियों पर 1000-1000 रुपए और शेष पर 500-500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतानी होगी।

दुर्घटनाएँ -चिकित्सक घायल, कार चालक घायल



न्यायसाक्षी @रायगढ़। जिले में अलग अलग सड़क दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गये हैं। जिन्हे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार पहली घटना में पीएचसी बरां जोबी में प्रभारी चिकित्सक के पद पर कार्यरत डॉ. मनोज त्रिपाठी, उम्र 44 वर्ष, 5 मई को पीएचसी बरां से मिटिंग में सम्मिलित होने के लिये अपने मोटर सायकल से रायगढ़ आ रहे थे कि करीब मेन रोड ग्राम तरकेला पावरग्रिड के पास बोलरो वाहन नम्बर सीजी13 यूजी113 के चालक ने डॉ. त्रिपाठी को ठोकर मारकर दिया, जिससे डॉ. त्रिपाठी की

ट्रेन से कूटी लड़की

न्यायसाक्षी @रायगढ़। आज उस समय कोहराम मच गया जब टाटा बिलासपुर पैसेंजर ट्रेन से एक युवती ने छलांग लगा दी। आनन फानन में जंजीर खींच कर ट्रेन को रोकना गया और यात्रियों के दल ने उसे खोजबीन की तो एक किमी दूर गंभीर रूप से घायल युवती ने आवाज दे कर लोगों को बताया की वो जिंदा है। घायल युवती शिनाख्त नहीं हो सकी है। यह हादसा आज सुबह साढ़े पांच बजे के लगभग हुआ टाटा बिलासपुर पैसेंजर जैसे ही झागडीह स्टेशन से निकली कि ट्रेन में चौखण्डर मच गई। दो युवकों ने बताया कि एक युवती ट्रेन से कूट गई, जिसे बाद में गंभीर हालत में एडमिट किया गया।

खाईवाल पकड़ाया, कोतवाली पुलिस की कार्यवाही

न्यायसाक्षी @रायगढ़। कोतवाली पुलिस पेट्रेलिंग के दौरान केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड के बाहर चाय ठेला चलाने वाले लक्ष्मी नारायण बरेठ को सट्टा पकड़ लिखते पकड़ा गया है। आरोपी के पास से नगदी 4360 रु एवं एक नीली स्याही वाली डाट पेन तथा कागज में लेख लाखों रूपये के सट्टा पट्टी जस की गई है। आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली रायगढ़ में धारा 4 क सट्टा अधिनियम

बांये पैर की चार उगलों कटकर अलग हो गया तथा बांये पिंडली में चोट आया है। डॉ. त्रिपाठी का ईलाज संजीवनी अस्पताल में किया जा रहा है। दूसरी घटना में ग्राम झरन थाना लैलूंगा निवासी सुखराम सारथी उम्र 40 वर्ष झुयवरी करता है। 15 मई को सुखराम सारथी डस्टर वाहन लेकर छल आया था। सुबह छल से वापस लैलूंगा जाते समय देउरमार के पास में घरघोडा तरफ से आ रही ट्रेलर वाहन सीजी12 सी 3371 का चालक ने डस्टर वाहन को सामने से ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया। जिससे डस्टर वाहन रोड किनारे पलट गई गाड़ी का सामने का भाग क्षतिग्रस्त हो गया है। एक्सीडेंट से सुखराम सारथी के मुंह ओठ के पास व सीने में चोट आई है।

सेपटी अधिकारी, शिप्ट इंचार्ज पर प्रकरण दर्ज

न्यायसाक्षी @रायगढ़। अंजनी स्टील प्लांट में 9 मई को कोइलटर्गई में रहने वाला धवल कुमार पटेल उम्र 31 वर्ष का रेलिंग मशीन में काम करते समय प्लांट का सिर किलन मशीन और रेलिंग मशीन के बीच आ जाने से मौत हो गया था। मामले में मर्ग जांच पर मशीनरी वस्तु रेलिंग मशीन में बिना सुरक्षा व्यवस्था के सेपटी अधिकारी योगेश उपाध्याय एवं शिप्ट इंचार्ज धनेश्वर लाल यादव द्वारा उम्मा पूर्वक कार्य करने से घटना घटित होना पाये जाने पर दोनों के विरुद्ध धारा 287, 304, 34 आई.पी.सी. दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने केमिकल फैक्ट्री में हुए हादसे की जांच के निर्देश दिए

औद्योगिक इलाकों में रसायन फैक्ट्रियों की छापामार शैली में जांच शुरू



न्यायसाक्षी @रायगढ़। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राजधानी रायपुर के भनपुरी इलाके में कल एक केमिकल पेंट फैक्ट्री में हुए विस्फोट में तीन लोगों की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए मामले को गंभीरता से लिया है। उनके निर्देश पर घटना की

मुख्यमंत्री से श्री भूपेश बघेल और प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात



न्यायसाक्षी @रायगढ़। मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने आज शाम यहां मंत्रालय, महानदी भवन, में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री भूपेश

पिता ने की पुत्र की निर्मम हत्या, गिरफ्तार

न्यायसाक्षी @रायगढ़। लैलूंगा नहर पारा वार्ड क्र. 6 में रहने वाले बोधराम सारथी, उम्र 48 वर्ष, ने 15 मई की रात्रि मामूली विवाद को लेकर अपने एकलौते लड़के राजू सारथी उम्र 24 वर्ष के गले में टांगिया से मारकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

चलती कार धू धू कर जल उठी

न्यायसाक्षी @रायगढ़। मारुती डिजायर कार जो मेकेनिक जावेद खान रायगढ़ की बतायी जाती है, रायगढ़ से खरसिया जा रही थी, कि चपले के पास अकस्मात दोपहर 1 बजे कार के पिछले हिस्से से आग की लपटें उठने लगी और देखते ही देखते उसने कार को अपनी चपेट में ले लिया कार में उस वक्त तीन लोग सवार थे, जो किसी तरह बाहर निकले और जान बचायी मामले में शाट सर्किट के कारण आग लगना बताया जा रहा है। कार का नम्बर सीजी13 वीडी 3241 है।

कोर्ट जाएंगे BSF के बर्खास्त जवान तेजबहादुर

नई दिल्ली: खराब खान का लेकर सुर्खियों में आए बीएसएफ के जवान को बर्खास्त करने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है, विरोधी दलों ने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और आरोप लगाए हैं कि सरकार लोगों से बोलने की आजादी खीन रही है, उधर बर्खास्त जवान ने अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। बता दें कि जम्मू के पूंछ में एलओसी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के एक जवान तेज बहादुर यादव ने इस साल की शुरुआत में अपने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने सीमा पर तैनात जवानों को दिए जा रहे खराब खाने को जनता को दिखाया था। वीडियो वायरल होते ही केंद्र सरकार ने इस मामले पर जांच बैठा दी थी, बीएसएफ ने

दण्डाधिकारी जांच का निर्णय लिया गया है और छापामार शैली में इस प्रकार के सभी रसायन उद्योगों की जांच भी शुरू कर दी गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ओ.पी.चौधरी ने कल हुई इस औद्योगिक दुर्घटना की दण्डाधिकारी जांच का आदेश आज यहां जारी कर दिया। जिला दण्डाधिकारी ने डिटी कलेक्टर सुश्री शीतल बंसल को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच अधिकारी द्वारा फैक्ट्री में विस्फोट के कारणों तथा सुरक्षा उपायों की सहित अन्य पहलुओं की विस्तृत जांच की जाएगी।

कुरुडीह जमीन मामला

बघेल के नतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल को विश्वास दिलाया कि कुरुडीह के जमीन के मसले पर निष्पक्ष और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा अभिलेख में अभी यह जमीन शासकीय है। मामले का निराकरण कानूनी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

अपहृत युवक, तारापुर में मिला

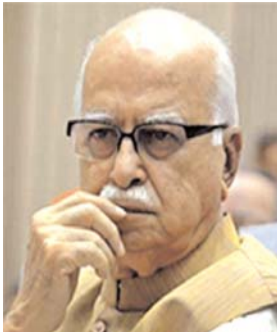
न्यायसाक्षी @रायगढ़। थाना खरसिया अन्तर्गत ग्राम सोण्डका में रहने वाले 25 वर्षीय युवक पप्पू तरुण कुमार सिदार उम्र करीब 25 वर्ष को 15 मई के 04.00 बजे शाम अज्ञात चार व्यक्तियों ने बोलेरो वाहन में बिठाकर रायगढ़ की ओर ले आये जो कोतरारोड अन्तर्गत ग्राम तारापुर के पुलिसिया के पास घायल अवस्था में मिला। जिसे के.जी.एच. रायगढ़ में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत सामान्य है। घटना के संबंध में थाना खरसिया में अज्ञात चार व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 365,34 भा.दं.वि. दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

फ्राइम ब्रांच, कोसीर थाने की कार्यवाही

न्यायसाक्षी @रायगढ़। कोसरी पुलिस ने अलग अलग स्थानों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गये आरोपियों के पास से लाखों रूपए की संपत्ति भी बरामद किया गया है।

बाबरी मस्जिद केस

बड़े नेताओं को अपराध साबित होने पर हो सकती है सजा



नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार, 19 अप्रैल को आपराधिक साजिश के अपराध को बहाल किया था, जिसके बाद राजनीतिक रूप से संवेदनशील बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा के दिग्गज नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और अन्य वीवीआईपी पर जिन आरोपों में सुनवाई होनी है, उनमें दो से पांच साल तक के कारावास की सजा का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार 19 अप्रैल को आपराधिक साजिश के अपराध को बहाल किया, यह आरोप इस मामले में उन पर लगे आरोपों में वास्तविक रूप से शामिल था। उनके खिलाफ भारतीय डंड सहिता भादंस के अपराधों के तहत सुनवाई होगी जिनमें धर्म आदि के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच कथित रूप से वैमनस्य बढना, राष्ट्रीय एकता के लिए नुकसानदेह बयान टिप्पणियां करना और सार्वजनिक नुकसान वाले बयान देना शामिल है, इन अपराधों के लिए भादंस में अधिकतम पांच साल के कारावास की सजा का प्रावधान है। धर्म का अपमान करने की मंशा से किसी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने के आरोप में अधिकतम दो साल की सजा जबकि धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करके किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने की मंशा से द्वेषपूर्ण कृत्य में अधिकतम तीन साल के कारावास की सजा का प्रावधान है। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की अपील को स्वीकार करते हुए भाजपा के नेताओं लालकृष्ण आडवाणी और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप को बहाल कर दिया है। इस मामले में हुई घटनाओं का घटनाक्रम इस प्रकार है :

खिलाफ दर्ज की गई, दूसरी प्राथमिकी में भाजपा के नेताओं आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अन्य को ढांच गिराए जाने से पहले कथित तौर पर सांप्रदायिक भाषण देने के लिए नामजद किया गया।

अक्टूबर 1993: सीबीआई ने आडवाणी और अन्य पर साजिश का आरोप लगाते हुए एक समग्र आरोप पत्र दायर किया।

चार मई 2001: विशेष सीबीआई अदालत ने आडवाणी जोशी उमा भारती बाल ठकुर और अन्य के खिलाफ कार्यवाही बंद की।

दो नवंबर 2004: सीबीआई ने भाजपा के नेताओं के खिलाफ कार्यवाही बंद किए जाने को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ के समक्ष तकनीकी आधार पर चुनौती दी।

20 मई 2010: उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज की और कहा कि सीबीआई की पुनर्विचार याचिका में कोई दम नहीं।

फरवरी 2011: सीबीआई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंची, छह मार्च 2017, उच्चतम न्यायालय ने संकेत दिया कि वह बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा के नेताओं के खिलाफ साजिश के आरोप को बहाल करने पर विचार कर सकता है।

21 मार्च 2017: उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए ताजा प्रयासों का सुझाव दिया।

छह अप्रैल 2017: उच्चतम न्यायालय ने समयब तरीके से मामले की सुनवाई पूरी करने को कहा और सीबीआई की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा।

19 अप्रैल 2017: उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में आडवाणी जोशी और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री उमा भारती के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप को बहाल किया और अति विशिष्ट लोगों और कारसेवकों के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई को एकसाथ जोड़ दिया।

जोडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने कहा कि चुपचाप सरकार के नाम की माला जपते रहो अगर किसी ने सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत की तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोगों से बोलने की आजादी खीन रही है।

उधर, तेजबहादुर पर की गई इस कार्रवाई को लेकर राजनीति में भी विरोध के सुर उठने लगे हैं, इस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजौजू ने



उच्चतम न्यायालय ने बुधवार, 19 अप्रैल को आपराधिक साजिश के अपराध को बहाल किया था, जिसके बाद राजनीतिक रूप से संवेदनशील बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा के दिग्गज नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और अन्य वीवीआईपी पर जिन आरोपों में सुनवाई होनी है, उनमें दो से पांच साल तक के कारावास की सजा का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार 19 अप्रैल को आपराधिक साजिश के अपराध को बहाल किया, यह आरोप इस मामले में उन पर लगे आरोपों में वास्तविक रूप से शामिल था। उनके खिलाफ भारतीय डंड सहिता भादंस के अपराधों के तहत सुनवाई होगी जिनमें धर्म आदि के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच कथित रूप से वैमनस्य बढना, राष्ट्रीय एकता के लिए नुकसानदेह बयान टिप्पणियां करना और सार्वजनिक नुकसान वाले बयान देना शामिल है, इन अपराधों के लिए भादंस में अधिकतम पांच साल के कारावास की सजा का प्रावधान है। धर्म का अपमान करने की मंशा से किसी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने के आरोप में अधिकतम दो साल की सजा जबकि धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करके किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने की मंशा से द्वेषपूर्ण कृत्य में अधिकतम तीन साल के कारावास की सजा का प्रावधान है। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की अपील को स्वीकार करते हुए भाजपा के नेताओं लालकृष्ण आडवाणी और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप को बहाल कर दिया है। इस मामले में हुई घटनाओं का घटनाक्रम इस प्रकार है :

खिलाफ दर्ज की गई, दूसरी प्राथमिकी में भाजपा के नेताओं आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अन्य को ढांच गिराए जाने से पहले कथित तौर पर सांप्रदायिक भाषण देने के लिए नामजद किया गया।

अक्टूबर 1993: सीबीआई ने आडवाणी और अन्य पर साजिश का आरोप लगाते हुए एक समग्र आरोप पत्र दायर किया।

चार मई 2001: विशेष सीबीआई अदालत ने आडवाणी जोशी उमा भारती बाल ठकुर और अन्य के खिलाफ कार्यवाही बंद की।

दो नवंबर 2004: सीबीआई ने भाजपा के नेताओं के खिलाफ कार्यवाही बंद किए जाने को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ के समक्ष तकनीकी आधार पर चुनौती दी।

20 मई 2010: उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज की और कहा कि सीबीआई की पुनर्विचार याचिका में कोई दम नहीं।

फरवरी 2011: सीबीआई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंची, छह मार्च 2017, उच्चतम न्यायालय ने संकेत दिया कि वह बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा के नेताओं के खिलाफ साजिश के आरोप को बहाल करने पर विचार कर सकता है।

21 मार्च 2017: उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए ताजा प्रयासों का सुझाव दिया।

छह अप्रैल 2017: उच्चतम न्यायालय ने समयब तरीके से मामले की सुनवाई पूरी करने को कहा और सीबीआई की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा।

19 अप्रैल 2017: उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में आडवाणी जोशी और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री उमा भारती के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप को बहाल किया और अति विशिष्ट लोगों और कारसेवकों के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई को एकसाथ जोड़ दिया।

जोडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने कहा कि चुपचाप सरकार के नाम की माला जपते रहो अगर किसी ने सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत की तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोगों से बोलने की आजादी खीन रही है।

उधर, तेजबहादुर पर की गई इस कार्रवाई को लेकर राजनीति में भी विरोध के सुर उठने लगे हैं, इस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजौजू ने